Punjab Kesari Edition Delhi
11.2.2017 Page 11
Height 21.60cm Width 14.17 cm

साल के अंत तक 1,000 गांव बनेंगे डिजिटल

14 लाख आंगनबाड़ी कर्मी बनेंगे डिजिटल साक्षर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि साल के अंत तक 1,000 गांवों को डिजिटल गांव बना दिया जाएगा, जहां टेली-मेडिसिन व टेली-एजुकेशन जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार 65,000 ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी कंप्यूटर से जोड़ने जा रही है। वहीं 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मचारियों को डिजिटल साक्षर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा।

ई-वॉलेट के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सरकार जल्द ही डिजिटल पेमेंट रूल्स फॉर वॉलेट लाने जा रही है। वहीं आगामी 30 जून तक देश भर की 5.58 लाख राशन की दुकानों को आधार नंबर आधारित पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रसाद ने बताया कि डिजिटल गांवों में सेवा क्षेत्र का विकास निजी व सरकारी दोनों संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा। साल के अंत तक 1,000 गांवों को डिजिटल गांव बना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिजिटल पेमेंट रूल्स फॉर वॉलेट का मसौदा जल्द ही लोगों की राय के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखा गया है।

जून अंत तक सभी राशन दुकानों में होंगी आधार आधारित पीओएस मशीनें

प्रसाद ने बताया कि राशन की दुकानों को आधार से जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर 30 जून तक देश की सभी राशन दुकानों को आधार आधारित पीओएस से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल गुजरात, राजस्थान व आंध्र प्रदेश की सभी राशन की दुकानें आधार आधारित पीओएस से जुड़ गई हैं। उन्होंने बताया कि आधार आधारित मशीन से राशन की दुकानों को जोड़ने की वजह से पहले के मुकाबले 14.68 फीसदी गेहूं की बचत हुई है तो 20 फीसदी चीनी व 39 फीसदी मिट्टी के तेल की बचत हुई है।

10 खरब डॉलर की हो जाएगी डिजिटल अर्थव्यवस्था

प्रसाद ने बताया कि अगले पांच-सात साल में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर की हो जाएगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था में आईटी, डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स व इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग व टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़ी चीजें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में होने वाले निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में फिलहाल 11 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है, जो मूल्य के हिसाब से 54,000 करोड़ रुपये का है। अगले साल तक देश में मोबाइल फोन निर्माण 90,000 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। फिलहाल देश में 108 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है और 50 करोड़ लोग इंटरनेट की सुविधा ले रहे हैं, जबकि 35 करोड़ लोग स्मार्टफोन रखते हैं।